Toppersnotes
Unleash the topper in you

1st - ग्रेड

अर्थशास्त्र

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)

पेपर 2 || भाग – 4

SIERRA INNOVATIONS

Index

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1.	**राजस्थान की अर्थव्यवस्था** ➢ राजस्थान में आर्थिक नियोजन की संरचना, रणनीति और उद्देश्य ➢ राजस्थान की अर्थव्यवस्था की संरचना: क्षेत्रीय संरचना, रोजगार पैटर्न और संरचनात्मक परिवर्तन (1956-2025) ➢ राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन: भूमि, खनिज, वन, जल और ऊर्जा क्षमता ➢ राजस्थान के मानव संसाधन: जनसांख्यिकी प्रोफ़ाइल, कार्यबल, शिक्षा और मानव विकास ➢ राजस्थान में कृषि: प्रकृति, फसल पद्धति और उत्पादकता रुझान ➢ राजस्थान में कृषि सुधार, योजनाएँ और नवाचार ➢ राजस्थान में सिंचाई: परियोजनाएँ, नहरें, भूजल और जल प्रबंधन रणनीतियाँ ➢ राजस्थान की पशुधन और डेयरी अर्थव्यवस्था: संरचना, उत्पादकता और नीतिगत पहल ➢ राजस्थान में औद्योगिक विकास: संरचना, विकास, नीतियां और उभरते क्षेत्र ➢ राजस्थान में सेवा क्षेत्र: पर्यटन, व्यापार, आईटी और वित्तीय सेवाओं का विकास विश्लेषण ➢ राजस्थान में बुनियादी ढांचा विकास: सड़क, ऊर्जा, डिजिटल और औद्योगिक गलियारे ➢ राजस्थान में विकास परियोजनाएं और योजनाएं: प्रमुख कल्याण और रोजगार कार्यक्रम ➢ कल्याण और सामाजिक विकास योजनाएँ: गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समावेशन ➢ राजस्थान की अर्थव्यवस्था की समस्याएँ और संभावनाएँ: संरचनात्मक मुद्दे, क्षेत्रीय असंतुलन और भविष्य की रणनीतियाँ ➢ व्यापक सारांश और एकीकृत मानसिक मानचित्र: संरचना, चुनौतियाँ और नीति दृष्टिकोण	
2.	**अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र** ➢ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवलोकन और अवधारणा ➢ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का शास्त्रीय सिद्धांत: एडम स्मिथ का पूर्ण लाभ का सिद्धांत ➢ रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत ➢ अवसर लागत सिद्धांत (गॉटफ्राइड हैबरलर, 1936) ➢ हेक्सचर -ओहलिन सिद्धांत (कारक बंदोबस्ती सिद्धांत) ➢ कारक मूल्य समतुल्यीकरण और संबंधित प्रमेय ➢ व्यापार की शर्तें (TOT) और व्यापार से लाभ ➢ व्यापार से लाभ: मापन, प्रकार और वितरण ➢ मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण: सिद्धांत, तर्क और नीतिगत दृष्टिकोण ➢ टैरिफ और कोटा: अवधारणाएं, प्रकार और कल्याण विश्लेषण ➢ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवलोकन और अवधारणा ➢ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का शास्त्रीय सिद्धांत (एडम स्मिथ: पूर्ण लाभ) ➢ डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत ➢ अवसर लागत सिद्धांत (हैबरलर का तुलनात्मक लाभ का पुनर्निरूपण) ➢ हेक्स्चर-ओहलिन सिद्धांत (कारक बंदोबस्ती सिद्धांत) ➢ कारक मूल्य समतुल्यीकरण, स्टॉलपर-सैमुअलसन और राइबसिन्स्की प्रमेय ➢ व्यापार की शर्तें (टीओटी): अवधारणाएं, प्रकार, निर्धारक और पारस्परिक मांग सिद्धांत ➢ व्यापार से लाभ: मापन, वितरण, स्थैतिक और गतिशील लाभ ➢ मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण: अवधारणाएँ, तर्क और रणनीतिक व्यापार नीति ➢ टैरिफ और कोटा: प्रकार, प्रभाव और कल्याण विश्लेषण	

	➢ भुगतान संतुलन (बीओपी): संरचना, घटक, असंतुलन और समायोजन तंत्र ➢ भुगतान संतुलन असंतुलन: समायोजन के सिद्धांत (लोच, अवशोषण और मौद्रिक दृष्टिकोण) ➢ विदेशी मुद्रा दर: निर्धारण, सिद्धांत और विनिमय दर प्रणालियाँ ➢ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान: आईएमएफ, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ, ब्रिक्स और वैश्विक व्यापार शासन ➢ भारत का विदेश व्यापार: संरचना, दिशा और परिमाण (स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान तक) ➢ भारत में व्यापार सुधार: नीतियां, उदारीकरण और निर्यात संवर्धन ढांचा ➢ भारत में निर्यात संवर्धन उपाय: योजनाएँ, संस्थागत ढाँचा और प्रदर्शन मूल्यांकन ➢ भारत की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति: रणनीतियाँ, एफटीए, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका और भविष्य की दिशाएँ ➢ भारत का भुगतान संतुलन और विनिमय दर प्रबंधन: आरबीआई की भूमिका, नीति समन्वय और व्यापक आर्थिक स्थिरता ➢ एकीकृत समीक्षा: सिद्धांत, नीतियां, संस्थाएं और भारत की वैश्विक व्यापार स्थिति (व्यापक सारांश और संशोधन) ➢ वैश्विक व्यापार गतिशीलता: समकालीन मुद्दे, सुधार और भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण	
3.	**विकास के सिद्धांत और मॉडल** ➢ आर्थिक विकास की अवधारणा और मापन: अर्थ, दायरा, निर्धारक और रुझान ➢ आर्थिक विकास के शास्त्रीय सिद्धांत: आधार, मूल विचार और विश्लेषणात्मक ढांचा ➢ एडम स्मिथ का आर्थिक विकास मॉडल: श्रम विभाजन, पूंजी संचय और बाजार विस्तार ➢ डेविड रिकार्डो का आर्थिक विकास मॉडल: पूंजी संचय, घटता प्रतिफल, किराया और स्थिर अवस्था ➢ आर्थिक विकास पर माल्थसियन और मार्क्सवादी दृष्टिकोण: जनसंख्या, अधिशेष मूल्य और संकट की प्रवृत्तियाँ ➢ शास्त्रीय से नव-शास्त्रीय विकास में परिवर्तन: आलोचना, विकास और पूंजी-प्रौद्योगिकी मॉडल का उदय ➢ हैरोड-डोमर मॉडल: मान्यताएँ, समीकरण, स्थिरता और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अनुप्रयोग ➢ सोलो-स्वान नव-शास्त्रीय विकास मॉडल: मान्यताएँ, स्थिर अवस्था, तकनीकी प्रगति और नीतिगत निहितार्थ ➢ तुलनात्मक मूल्यांकन: हैरोड-डोमर बनाम सोलो मॉडल - स्थिरता, बचत, आईसीओआर और नीतिगत निहितार्थ ➢ दोहरे क्षेत्र विकास का लुईस मॉडल: अधिशेष श्रम, संरचनात्मक परिवर्तन और नीतिगत निहितार्थ ➢ वितरण और विकास का काल्डोर मॉडल: कीनेसियन मूल, कारक शेयर और शैलीगत तथ्य ➢ संतुलित बनाम असंतुलित विकास सिद्धांत: नर्कसे, रोसेनस्टाइन-रोडन और हिर्शमैन ➢ अंतर्जात वृद्धि सिद्धांत: रोमर मॉडल - ज्ञान, नवाचार और बढ़ते प्रतिफल ➢ अंतर्जात विकास सिद्धांत: लुकास मॉडल - मानव पूंजी, करके सीखना, और शिक्षा नीति ➢ विकास सिद्धांतों का एकीकृत अवलोकन: तुलनात्मक विश्लेषण, विकास और समकालीन प्रासंगिकता	
4.	**शिक्षणशास्त्र और निर्देशात्मक रणनीतियाँ** ➢ परिचय और संचार कौशल ➢ मौखिक संचार कौशल ➢ गैर-मौखिक संचार कौशल	

	➢ शिक्षण मॉडल: परिचय और अवलोकन ➢ अग्रिम आयोजक (सूचना प्रसंस्करण) ➢ पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल ➢ समूह जांच (सामाजिक संपर्क) ➢ गैर-निर्देशात्मक मॉडल (व्यक्तिगत विकास) ➢ शिक्षण-अधिगम सामग्री की तैयारी और उपयोग ➢ सहकारी शिक्षा और रचनावादी दृष्टिकोण	
5.	**ICT और डिजिटल शिक्षा** ➢ ICT और डिजिटल शिक्षाशास्त्र ➢ ई-लर्निंग और वर्चुअल कक्षाएं ➢ शिक्षण में प्रौद्योगिकी का एकीकरण ➢ सीखने में प्रौद्योगिकी का एकीकरण ➢ मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण ➢ अर्थशास्त्र में ऑनलाइन संसाधन और डेटा विश्लेषण उपकरण ➢ डिजिटल अर्थशास्त्र शिक्षा में चुनौतियाँ और सर्वोत्तम अभ्यास ➢ अर्थशास्त्र शिक्षा में शिक्षणशास्त्र, अनुदेशात्मक रणनीतियाँ और आईसीटी	

1 UNIT

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

राजस्थान में आर्थिक नियोजन की संरचना, रणनीति और उद्देश्य

1. परिचय

1.1 अवलोकन

- राजस्थान, **भारत का सबसे बड़ा राज्य (भारत के क्षेत्रफल का 10.4%)** , अपनी **शुष्क भूगोल, खनिज संपदा, कृषि क्षमता और मानव संसाधन विविधता द्वारा आकारित एक विविध आर्थिक संरचना का प्रतिनिधित्व करता है।**
- राज्य की अर्थव्यवस्था **मुख्यतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से परिवर्तित होकर कृषि, खनन, उद्योग और सेवाओं** द्वारा संचालित **बहु-क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था** में परिवर्तित हो गई है।
- आर्थिक सुधारों के बाद और सक्रिय राज्य नीतियों ने राजस्थान को **संतुलित क्षेत्रीय विकास और सतत वृद्धि की ओर अग्रसर किया है।** राजस्थान का आर्थिक विकास पारिस्थितिकी बाधाओं के तहत संसाधन अनुकूलन की कहानी है।

2. राजस्थान की मूल आर्थिक रूपरेखा

सूचक	**विवरण (2024-25 अनुमानित)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	₹15.2 लाख करोड़
प्रति व्यक्ति आय	₹1.72 लाख
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी	~4.9%
जनसंख्या (जनगणना प्रक्षेपण)	~8.1 करोड़
शहरीकरण स्तर	~26%
साक्षरता दर	69.7%
श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर)	54%
मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)	0.66 (मध्यम मानव विकास सूचकांक समूह)
जीएसडीपी वृद्धि दर (2023-24)	~6.8%

राजस्थान **जीएसडीपी में शीर्ष 10 भारतीय राज्यों में शामिल है** , लेकिन **पश्चिमी शुष्क और पूर्वी सिंचित क्षेत्रों के बीच असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है।**

3. राजस्थान की अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक संरचना

3.1 जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान (2024-25) राजस्थान की अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं और संरचना

1. परिचय

1.1 संदर्भ

- भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान **(3.42 लाख वर्ग किमी) ,** देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग **10.4% है, लेकिन इसकी जनसंख्या (2021 अनुमान) का केवल 5.6% है ।**
- **संसाधन संपन्न** होने के बावजूद , राजस्थान को शुष्क जलवायु, कम वर्षा और असमान क्षेत्रीय विकास के कारण **विकास संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।**
- पिछले सात दशकों में राजस्थान एक **निर्वाह कृषि अर्थव्यवस्था से** विकसित औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के साथ एक **विविध अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया है।**
  राजस्थान की अर्थव्यवस्था भारत की अपनी विकास गाथा को प्रतिबिम्बित करती है - कृषि क्षेत्र में स्थिरता से लेकर क्षेत्रीय असमानताओं के साथ विविध विकास तक।

2. राजस्थान की अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं

विशेषता	**विवरण**
भौगोलिक	सबसे बड़ा राज्य (भारत के क्षेत्रफल का 10.4%); पश्चिमी जिलों में रेगिस्तानी परिस्थितियों के साथ अधिकांशतः शुष्क और अर्ध-शुष्क।
जनसांख्यिकीय	जनसंख्या ~8.1 करोड़ (अनुमानित 2023); ग्रामीण हिस्सा 75%; घनत्व ~200 प्रति वर्ग किमी.
आर्थिक प्रकृति	मिश्रित अर्थव्यवस्था: कृषि आधार, विस्तारित औद्योगिक और सेवा क्षेत्र।

Toppers Notes Unleash the topper in you

विकास स्वरूप	प्रति वर्ष ~6-7% की स्थिर वास्तविक जीएसडीपी वृद्धि (औसत 2011-2024)।
संरचनात्मक संरचना	प्राथमिक (प्रमुख) से तृतीयक-प्रधान अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव।
क्षेत्रीय विविधता	विकसित क्षेत्रों (जयपुर, कोटा, उदयपुर) और पिछड़े क्षेत्रों (बाड़मेर , जैसलमेर, डूंगरपुर) के बीच तीव्र अंतर।
मानव विकास	एचडीआई (2022): 0.66; साक्षरता दर: 71%; लिंग अंतर उच्च।
प्राकृतिक निधियाँ	खनिजों से समृद्ध (जिप्सम, जस्ता, संगमरमर, चूना पत्थर, तांबा); विशाल सौर और पवन क्षमता।

राजस्थान में **संसाधनों की प्रचुरता के साथ-साथ मानव विकास की चुनौतियां भी विद्यमान हैं** - जो अभाव के बीच समृद्धि का विरोधाभास है।

3. राजस्थान की अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक विकास

3.1 1950 से पहले: रियासतें और कृषि में ठहराव

- निम्न औद्योगिक आधार और सामंती कृषि संरचना वाली खंडित रियासतें।
- निर्वाह कृषि और सीमित सिंचाई पर निर्भरता।

3.2 1950-1970: आधार चरण (पंचवर्षीय योजनाएँ)

- **भूमि सुधार, सिंचाई** और **सामुदायिक विकास** पर जोर ।
- कृषि प्रभुत्व (एनएसडीपी में 65% से अधिक हिस्सेदारी)।
- **रीको** और **औद्योगिक सम्पदा** के माध्यम से औद्योगीकरण की शुरुआत ।

3.3 1970-1990: हरित क्रांति और बुनियादी ढांचे का विस्तार

- सिंचाई का विस्तार (चंबल, इंदिरा गांधी नहर)।
- कृषि विविधीकरण और ग्रामीण विद्युतीकरण।
- लघु एवं हस्तशिल्प उद्योग विकसित हुए।

3.4 1991-2010: आर्थिक उदारीकरण और संरचनात्मक विविधीकरण

- औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र की वृद्धि में तेजी आई।
- पर्यटन, सीमेंट, वस्त्र और खनिज प्रमुख विकास चालक बन गए।
- रोजगार धीरे-धीरे गैर-कृषि क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो गया।

3.5 2010-2025: समावेशी और सतत विकास युग

- **नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल बुनियादी ढांचे और मानव विकास** पर ध्यान केंद्रित करें ।
- **एसडीजी और विजन 2030** के अनुरूप ।
- कोविड-19 व्यवधानों के बावजूद जीएसडीपी वृद्धि स्थिर; औद्योगिक गलियारे उभर रहे हैं।

राजस्थान में सुधार के बाद का परिवर्तन **क्षेत्रीय पुनर्संतुलन और क्षेत्रीय विविधीकरण द्वारा चिह्नित किया गया है।**

4. अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय संरचना

4.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) संरचना (वर्तमान मूल्य, 2023-24)

क्षेत्र	जीएसडीपी में हिस्सेदारी (%)	रुझान	योगदान
प्राथमिक (कृषि, पशुधन, खनन)	33.4	अस्वीकृत करना	ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़.
द्वितीयक (विनिर्माण, निर्माण, विद्युत)	24.7	नियमित	सीमेंट, कपड़ा और खनिज आधारित उद्योगों द्वारा संचालित।
तृतीयक (सेवाएँ)	41.9	बढ़ती	पर्यटन, आईटी, व्यापार, शिक्षा, वित्त तेजी से बढ़ रहे हैं।

तृतीयक क्षेत्र **राज्य की आय में अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में उभरा है** , जो सेवा-आधारित आधुनिकीकरण को दर्शाता है।

5. जीएसडीपी वृद्धि प्रदर्शन

5.1 विकास दर के रुझान

अवधि	औसत वार्षिक जीएसडीपी वृद्धि (%)	प्रमुख विशेषताऐं
1951-1980	2.8	कम उत्पादकता, कृषि अर्थव्यवस्था.
1980-2000	5.1	औद्योगिक विविधीकरण और सिंचाई विस्तार।
2000-2010	6.5	विनिर्माण और खनन में तीव्र वृद्धि।
2010-2020	7.1	सेवा क्षेत्र में तेजी, सौर ऊर्जा निवेश।
2020-2024	6.8	महामारी के बाद लचीली रिकवरी।

राजस्थान का विकास पथ भारत के राष्ट्रीय औसत के समान है, लेकिन **जलवायु पर निर्भरता के कारण इसमें अधिक अस्थिरता है** ।

Unleash the topper in you

6. रोजगार संरचना

क्षेत्र	रोजगार हिस्सेदारी (%)	अवलोकन
कृषि एवं संबद्ध	55	अभी भी प्रमुखता है, जो छिपी हुई बेरोजगारी का संकेत देती है।
उद्योग	20	विनिर्माण और निर्माण केन्द्र उभर रहे हैं।
सेवाएं	25	पर्यटन, व्यापार, आईटी और लॉजिस्टिक्स का विस्तार।

रोजगार परिवर्तन, आय परिवर्तन से पीछे है - जो **बेरोजगारी या खराब रोजगार वृद्धि का संकेत है ।**

7. क्षेत्रीय संरचना और आर्थिक विविधता

7.1 राजस्थान के आर्थिक क्षेत्र

क्षेत्र	विशेषताएँ	प्रमुख जिले
पश्चिमी शुष्क (रेगिस्तान)	अल्प वर्षा, पशुधन एवं नहर सिंचाई पर निर्भरता।	जैसलमेर, बाड़मेर , बीकानेर.
पूर्वी अर्ध-शुष्क	मध्यम वर्षा, कृषि एवं लघु उद्योग।	जयपुर, अलवर , भरतपुर .
दक्षिणी जनजातीय-पहाड़ी	वन, खनिज, कम मानव विकास।	उदयपुर, डूंगरपुर , बांसवाड़ा ।
उत्तरी मैदान	सिंचित कृषि, औद्योगिक विकास।	कोटा, सीकर, झुंझुनू।

सिंचाई और बुनियादी ढांचे के विस्तार के बावजूद क्षेत्रीय असंतुलन बना हुआ है - जो एक प्रमुख नीतिगत चिंता है।

8. राजकोषीय और निवेश प्रोफ़ाइल

सूचक	मूल्य (2023-24)	अवलोकन
जीएसडीपी (वर्तमान)	₹15.3 लाख करोड़	छठी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था.
प्रति व्यक्ति आय	₹1.76 लाख	राष्ट्रीय औसत से कम (~₹1.97 लाख)।
राजकोषीय घाटा	जीएसडीपी का ~3.5%	एफआरबीएम सीमा के भीतर।
सार्वजनिक ऋण	जीएसडीपी का ~33%	मध्यम एवं टिकाऊ।
निवेश प्रवाह (2022-24)	₹2.1 लाख करोड़	मुख्य रूप से सौर ऊर्जा, सीमेंट, ऑटो और लॉजिस्टिक्स में।

बढ़ते पूंजीगत व्यय के साथ राजकोषीय स्थिरता राजस्थान के आर्थिक परिवर्तन का आधार है।

9. प्रमुख विकास चालक (2020)

1. **नवीकरणीय ऊर्जा** - सौर एवं पवन ऊर्जा (भड़ला , जैसलमेर, जोधपुर)।
2. **पर्यटन और विरासत** - जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, पुष्कर ।
3. **खनन एवं खनिज** - जस्ता (हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड), चूना पत्थर, संगमरमर।
4. **कपड़ा और हस्तशिल्प** - जयपुर, भीलवाड़ा , किशनगढ़ क्लस्टर।
5. **बुनियादी ढांचा एवं रसद** - दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी), समर्पित माल ढुलाई गलियारा।
6. **कृषि व्यवसाय एवं डेयरी** - दुग्ध सहकारी समितियां, कोल्ड चेन अवसंरचना।
   राजस्थान की नई अर्थव्यवस्था **नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और संसाधन आधारित उद्योगों पर आधारित है।**

10. संरचनात्मक विकास में चुनौतियाँ

चुनौती	स्पष्टीकरण
शुष्क जलवायु	कम वर्षा (<500 मिमी), सूखे का खतरा, कृषि को सीमित करता है।
पानी की कमी	भूजल पर अत्यधिक निर्भरता, घटता जलस्तर।
क्षेत्रीय असमानता	पश्चिमी रेगिस्तान बनाम पूर्वी सिंचित क्षेत्र।
रोजगार की गुणवत्ता	अनौपचारिक नौकरियों का बोलबाला; वेतन वृद्धि कम।
निम्न औद्योगिक आधार	कुछ क्लस्टरों के बाहर विनिर्माण अभी भी अविकसित है।
मानव पूंजी घाटा	ग्रामीण/आदिवासी जिलों में साक्षरता और स्वास्थ्य संबंधी अंतराल।

विकास मॉडल में संरचनात्मक बाधाओं पर काबू पाने के लिए **लचीलेपन, समावेशिता और स्थिरता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।**

11. PYQ एकीकरण

11.1 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

- राजस्थान की अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं और संरचना पर चर्चा करें।
- राजस्थान की अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय संरचना और विकास प्रदर्शन की व्याख्या करें।
- राजस्थान में आर्थिक विकास की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?
- राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय असंतुलन की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन कीजिए।

toppersnotes unleash the topper in you

11.2 PYQ रुझान

- **आरपीएससी/यूजीसी-नेट:** संकल्पनात्मक एवं डेटा आधारित प्रश्न।
- **आईएएस:** राज्य की अर्थव्यवस्था और नीति दिशा का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन।

12. सारांश नोड

- राजस्थान की अर्थव्यवस्था **मिश्रित संरचना प्रदर्शित करती है** जिसमें **कृषि प्रधानता धीरे-धीरे सेवा क्षेत्र के विस्तार के** आगे झुकती जा रही है ।
- विकास का प्रदर्शन स्थिर बना हुआ है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों और सेक्टरों में असमान है।
- आर्थिक परिवर्तन **प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, सिंचाई विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास से आकार लेता है।**
- **रोजगार, समानता और स्थिरता** में परिवर्तित करना चुनौती बनी हुई है ।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था की संरचना: क्षेत्रीय संरचना, रोजगार पैटर्न और संरचनात्मक परिवर्तन (1956-2025)

1. परिचय

1.1 आर्थिक संरचना की अवधारणा

- **किसी अर्थव्यवस्था की संरचना** उसके **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)** और **रोजगार में प्राथमिक (कृषि), द्वितीयक (उद्योग) और तृतीयक (सेवा)** क्षेत्रों के सापेक्ष योगदान को संदर्भित करती है ।
- एक स्वस्थ संरचनात्मक परिवर्तन **कृषि-प्रधान** से **उद्योग- और सेवा-प्रधान** विकास की ओर बदलाव का संकेत देता है।
- राजस्थान का संरचनात्मक परिवर्तन **विविधीकरण को प्रतिबिम्बित करता है** , फिर भी इसमें **द्वैतवादी चरित्र बरकरार है** - आधुनिक विकास क्षेत्र पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के साथ सह-अस्तित्व में हैं।
  राजस्थान की संरचनात्मक कहानी **निरंतर कृषि निर्भरता के साथ प्रगतिशील विविधीकरण की कहानी है** ।

2. राजस्थान की अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक संरचना (जीएसडीपी शेयर)

क्षेत्र	**1955-56**	**1980-81**	**2000-01**	**2010-11**	**2023-24**	**रुझान**
प्राथमिक	62.8%	48.1%	36.5%	31.4%	33.4%	धीरे-धीरे गिरावट, लेकिन अभी भी उच्च।
माध्यमिक	14.2%	20.3%	23.4%	25.1%	24.7%	मध्यम वृद्धि; औद्योगिक आधार परिपक्व हो रहा है।
तृतीयक	23.0%	31.6%	40.1%	43.5%	41.9%	लगातार वृद्धि; सेवा-आधारित विकास।

आधुनिकीकरण के बावजूद, **प्राथमिक क्षेत्र अभी भी महत्वपूर्ण बना हुआ है** - भूगोल, वर्षा पर निर्भरता और ग्रामीण आजीविका के कारण।

3. संरचनात्मक परिवर्तन की प्रकृति

3.1 प्रारंभिक चरण (1950-1980)

- **कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों** का प्रभुत्व ।
- औद्योगीकरण लघु उद्योग और हस्तशिल्प तक ही सीमित है।
- बुनियादी ढांचे और सिंचाई विस्तार (चंबल, आईजीएनपी) ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना शुरू कर दिया।

3.2 मध्यवर्ती चरण (1980-2000)

- आरआईआईसीओ और औद्योगिक नीतियों के तहत **खनन, सीमेंट और वस्त्र उद्योग** का विकास ।
- सेवा क्षेत्र (बैंकिंग, पर्यटन) का विस्तार होने लगा।
- कृषि के हिस्से में गिरावट; गैर-कृषि रोजगार की ओर विविधीकरण।

3.3 आधुनिक चरण (2000-2025)

- **सेवा क्षेत्र-आधारित विकास** : व्यापार, परिवहन, शिक्षा, आईटी और पर्यटन।
- **नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक गलियारों ने** द्वितीयक क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाया।
- शहरी-औद्योगिक जिलों और शुष्क ग्रामीण क्षेत्रों के बीच क्षेत्रीय अंतर बढ़ गया।
  राजस्थान में संरचनात्मक परिवर्तन **अरैखिक एवं असमान है** , जो प्रगति और असंतुलन दोनों को दर्शाता है।

4. रोजगार संरचना

4.1 क्षेत्रवार रोजगार वितरण

क्षेत्र	**रोजगार हिस्सेदारी (1980)**	**2000**	**2023-24**	**अवलोकन**
कृषि एवं संबद्ध	72%	64%	55%	अभी भी प्रभावी, धीमी गति से विविधीकरण।
उद्योग	10%	15%	20%	निर्माण, एमएसएमई के माध्यम से विस्तार।
सेवाएं	18%	21%	25%	व्यापार, परिवहन, पर्यटन, शिक्षा में वृद्धि।

4.2 संरचनात्मक विरोधाभास

- जीएसडीपी में कृषि का योगदान: **33%** , लेकिन रोजगार: **55%** → **छिपी हुई बेरोजगारी** बनी हुई है।
- सेवा क्षेत्र **जीएसडीपी में 42% का योगदान देता है** , लेकिन केवल **25% को रोजगार देता है** → कौशल और पहुंच संबंधी बाधाएं।
  राजस्थान का विकास **कम रोजगार-प्रधान** तथा **अत्यधिक अनौपचारिक** प्रकृति का है।

5. क्षेत्रीय गतिशीलता और विशेषताएं

5.1 प्राथमिक क्षेत्र

- **कृषि, पशुधन, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन** शामिल हैं ।
- अभी भी आधे से अधिक कार्यबल को रोजगार मिला हुआ है।
- प्रमुख बाधाएँ: कम वर्षा, खराब मृदा उर्वरता, खंडित जोत और जल की कमी।
- सकारात्मक प्रवृत्ति: **पशुधन और डेयरी का योगदान बढ़ रहा है** , ग्रामीण आय स्थिर हो रही है।

5.2 द्वितीयक क्षेत्र

- **खनिज आधारित उद्योगों** (सीमेंट, जस्ता, संगमरमर) और **वस्त्र** (भीलवाड़ा , पाली) का प्रभुत्व ।
- **निर्माण और बुनियादी ढांचा** क्षेत्र प्रमुख रोजगार सृजनकर्ता हैं।
- **रीको** , **डीएमआईसी** और **इन्वेस्ट राजस्थान 2022** के अंतर्गत औद्योगिक क्लस्टर क्षेत्रीय विकास को गति देंगे।

5.3 तृतीयक क्षेत्र

- सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र; **पर्यटन** , **शिक्षा** , **व्यापार** , **परिवहन** और **बैंकिंग का नेतृत्व** ।
- **भारत के घरेलू पर्यटन प्रवाह में** राजस्थान का योगदान 10% है ।
- जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के आसपास आईटी और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र उभर रहे हैं।
  तृतीयक क्षेत्र राजस्थान के **आधुनिक विकास का इंजन है** ।

6. संरचनात्मक चुनौतियाँ

चुनौती	विवरण
कम रोजगार लोच	सेवाओं और उद्योग में वृद्धि रोजगार सृजन के अनुपात में नहीं है।
क्षेत्रीय असमानताएँ	पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में औद्योगिक संकेन्द्रण; पश्चिमी रेगिस्तान पिछड़ा हुआ है।
जल और जलवायु पर निर्भरता	मानसून पर निर्भरता के कारण कृषि प्रदर्शन अस्थिर है।
मानव पूंजी घाटा	शिक्षा और कौशल में अंतर उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में श्रम गतिशीलता में बाधा डालता है।
अपर्याप्त औद्योगिक गहराई	उच्च मूल्य विनिर्माण का अभाव; प्राथमिक उत्पादों पर अत्यधिक निर्भरता।

राजस्थान का विकास **विभिन्न क्षेत्रों, सेक्टरों और जनसंख्या समूहों में असंतुलित बना हुआ है।**

7. क्षेत्रीय केस स्टडीज (उदाहरणात्मक नोड्स)

7.1 कृषि और पशुधन

- **पशुधन** (दूध, ऊन, ऊंट उत्पाद) में तेजी के कारण जीएसडीपी में हिस्सेदारी स्थिर (~ 33%) रही ।
- बाजरा और ग्वार गम में फसल विविधीकरण ; आधुनिक सिंचाई से पैदावार में सुधार।

7.2 खनन और उद्योग

- राजस्थान **भारत के खनिज उत्पादन में लगभग 15% का योगदान देता है।**
- प्रमुख खनिज: जस्ता, चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर।
- औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी, दिल्ली-जयपुर -किशनगढ़) द्वितीयक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

7.3 सेवा क्षेत्र

- **पर्यटन:** प्रतिवर्ष 60 मिलियन से अधिक घरेलू और 2 मिलियन से अधिक विदेशी पर्यटक।
- **व्यापार एवं परिवहन:** तीव्र राजमार्ग विकास; जयपुर और जोधपुर लॉजिस्टिक्स केन्द्र।
- **आईटी और स्टार्टअप:** राजस्थान स्टार्टअप नीति 2019 डिजिटल उद्यमिता का समर्थन करती है।
  राजस्थान का सेवा-आधारित मॉडल **प्राकृतिक संपदा + सांस्कृतिक पूंजी + नीतिगत सुधारों से प्रेरित है।**

8. क्षेत्रीय संरचनात्मक असंतुलन

क्षेत्र	प्रमुख क्षेत्र	महत्वपूर्ण मुद्दे
पश्चिमी (रेगिस्तान)	पशुधन, खनन	जल की कमी, कम औद्योगीकरण।
पूर्वी	कृषि, उद्योग	शहरीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास।
दक्षिणी (आदिवासी)	कृषि, वानिकी	गरीबी, कम साक्षरता, खराब कनेक्टिविटी।
उत्तरी	उद्योग, सेवाएँ	संतुलित विकास लेकिन शहरी भीड़भाड़।

राजस्थान के संरचनात्मक परिवर्तन को बनाए रखने के लिए संतुलित क्षेत्रीय विकास आवश्यक है ।

9. संरचनात्मक परिवर्तन संकेतक (1956-2025)

सूचक	1956	2025	अवलोकन
जीएसडीपी में कृषि का हिस्सा (%)	63	33	घटती भूमिका.
उद्योग हिस्सेदारी (%)	14	25	मध्यम वृद्धि.
सेवाओं का हिस्सा (%)	23	42	तेजी से विस्तार हो रहा है।
कृषि में रोजगार (%)	72	55	जीएसडीपी शेयर की तुलना में गिरावट धीमी है।
प्रति व्यक्ति आय (₹)	190	1,76,000	वास्तविक आय बढ़ी लेकिन असमान।

राजस्थान **कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से अर्ध-आधुनिक विविध अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया है** , फिर भी रोजगार की गुणवत्ता एक मुद्दा बनी हुई है।

10. PYQ एकीकरण

10.1 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

- राजस्थान की अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक संरचना पर चर्चा करें।
- 1956 से जीएसडीपी और रोजगार में क्षेत्रीय योगदान में हुए परिवर्तनों की व्याख्या करें।
- राजस्थान के आर्थिक विकास में संरचनात्मक असंतुलन का विश्लेषण करें।
- मूल्यांकन करें कि क्या राजस्थान की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है।

10.2 PYQ रुझान

- **आरपीएससी/यूजीसी-नेट:** संकल्पनात्मक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण प्रश्न।
- **आईएएस:** संरचना, रोजगार और समावेशिता को जोड़ने वाले विश्लेषणात्मक प्रश्न।

11. सारांश नोड

- राजस्थान की अर्थव्यवस्था में **स्पष्ट संरचनात्मक विविधीकरण** , लेकिन **आंशिक परिवर्तन दिखाई देता है** - जीएसडीपी में कृषि का हिस्सा गिरा है, फिर भी यह अभी भी रोजगार में प्रमुख है।
- आय सृजन में सेवाएं अग्रणी हैं; औद्योगिक विकास खनिजों और बुनियादी ढांचे पर आधारित है।
- सतत चुनौतियाँ: **क्षेत्रीय असंतुलन, बेरोजगारी वृद्धि और जल पर निर्भरता।**
- भविष्य के संरचनात्मक सुधारों में **रोजगार-प्रधान विनिर्माण, ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्रों और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।**

राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन: भूमि, खनिज, वन, जल और ऊर्जा क्षमता

1. परिचय

1.1 प्राकृतिक संसाधनों का महत्व

- **प्राकृतिक संसाधन राजस्थान की अर्थव्यवस्था की नींव** बनाते हैं , जो कृषि, उद्योग और समग्र विकास को प्रभावित करते हैं।
- राज्य में **प्रचुर खनिज संपदा** , **सौर ऊर्जा क्षमता** और **विविध पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद हैं, फिर भी** इसे गंभीर **जल संकट और भूमि क्षरण का सामना करना पड़ रहा है** ।
- मुख्य चुनौती संसाधनों के उपयोग में **सतत उपयोग और क्षेत्रीय समानता की है।**
  राजस्थान की आर्थिक ताकत इसकी मिट्टी के नीचे - **खनिजों और नवीकरणीय ऊर्जा में - निहित है** , लेकिन इसकी सबसे बड़ी बाधा मिट्टी के ऊपर है - **पानी की कमी** ।

2. भूमि संसाधन

2.1 भूमि क्षेत्र और उपयोग

वर्ग	क्षेत्रफल (मिलियन हेक्टेयर)	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का %
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	34.2	100
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	20.8	60.8
वन क्षेत्र	3.1	9.1
गैर-कृषि उपयोग	2.3	6.8
कृषि योग्य अपशिष्ट / बंजर	8.0	23.3

राजस्थान की लगभग एक-चौथाई भूमि **बंजर या रेगिस्तान** है , जिससे कृषि उत्पादकता बाधित होती है।

2.2 मिट्टी के प्रकार

मिट्टी का प्रकार	वितरण	विशेषताएँ / फसलें
रेगिस्तानी / रेतीली मिट्टी	पश्चिमी राजस्थान (बाड़मेर , जैसलमेर)	कम उर्वरता, बाजरा , ग्वार।
जलोढ़ मिट्टी	पूर्वी मैदान (भरतपुर , जयपुर)	उपजाऊ, गेहूँ, सरसों.
काली मिट्टी	दक्षिण-पूर्वी (कोटा, बूंदी)	कपास, सोयाबीन.
लाल और पीली मिट्टी	दक्षिणी पहाड़ियाँ (उदयपुर, डूंगरपुर)	दालें, मक्का.
शुष्क भूरी मिट्टी	केंद्रीय भाग	सीमित प्रजनन क्षमता.

सिंचाई, मृदा संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन पर निर्भर करती है ।

3. खनिज संसाधन

3.1 अवलोकन

- राजस्थान को **"खनिजों का खजाना" कहा जाता है** , जहां **80 से अधिक प्रकार** के प्रमुख और लघु खनिज पाए जाते हैं।
- **भारत के कुल खनिज उत्पादन में** लगभग 15% तथा **जस्ता और सीसा उत्पादन में 100% का योगदान देता है** ।

3.2 प्रमुख खनिज और उनके स्थान

खनिज	प्रमुख उत्पादक जिले	आर्थिक महत्व
जस्ता और सीसा	उदयपुर, राजसमंद , भीलवाड़ा	मिश्र धातु, बैटरी, मशीनरी में उपयोग किया जाता है।
चूना पत्थर	नागौर , चित्तौड़गढ़ , जैसलमेर	सीमेंट उद्योग की रीढ़.
संगमरमर और ग्रेनाइट	मकराना , किशनगढ़ , राजसमंद	हस्तशिल्प एवं निर्यातोन्मुख।
जिप्सम	बीकानेर, जोधपुर, नागौर	उर्वरक और सीमेंट उद्योग.
ताँबा	खेतड़ी (झुंझुनू)	विद्युतीय एवं औद्योगिक उपयोग।
फॉस्फेट (चट्टान)	झामरकोटड़ा (उदयपुर)	उर्वरक उद्योग.
लिग्नाइट	बाड़मेर , बीकानेर	तापीय ऊर्जा उत्पादन.

3.3 खनिज-आधारित उद्योग

- **हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (उदयपुर)** - एशिया का सबसे बड़ा एकीकृत जस्ता-सीसा प्रगालक।
- **जेके सीमेंट, बिरला सीमेंट, वंडर सीमेंट** - प्रमुख सीमेंट उत्पादक।
- **मकराना संगमरमर** - विश्व स्तर पर प्रसिद्ध; ताजमहल के जीर्णोद्धार में प्रयुक्त।
- **बाड़मेर लिग्नाइट परियोजना** - क्षेत्रीय बिजली और रोजगार को समर्थन देती है।

  खनिज क्षेत्र **जीएसडीपी में 8-10%** और **राज्य निर्यात में 30% का योगदान देता है** , जो **राजस्थान का औद्योगिक आधार बनाता है।**

Unleash the topper in you

4. वन संसाधन

4.1 वन क्षेत्र और वितरण

सूचक	मूल्य (2023-24)
कुल वन क्षेत्र	32,700 वर्ग किमी (कुल क्षेत्रफल का 9.6%)
घना जंगल	2.4%
खुला जंगल	4.9%
झाड़ीदार जंगल	2.3%

- प्रमुख वन क्षेत्र: **अरावली पहाड़ियाँ (उदयपुर, राजसमंद , सिरोही , कोटा)** ।
- प्रमुख प्रजातियाँ: **सागौन, खेजड़ी , बबूल , नीम और बबूल** ।

  वन क्षेत्र सीमित है, लेकिन रेगिस्तान संरक्षण और जल संरक्षण के लिए **पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है ।**

4.2 वन-आधारित आजीविका और उत्पाद

- गैर-लकड़ी वन उत्पाद: **गोंद, रेजिन, औषधीय पौधे, तेंदू पत्ते।**
- वन आधारित उद्योग: **फर्नीचर, हस्तशिल्प, हर्बल प्रसंस्करण।**
- **कार्बन पृथक्करण** और **जनजातीय आजीविका** में भूमिका (डूंगरपुर , बांसवाड़ा)।

4.3 मुद्दे

- वनों की कटाई, अतिचारण, खनन अतिक्रमण और सूखा।
- पुनर्वास के लिए **संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम)** और **कैम्पा कार्यक्रमों** का कार्यान्वयन ।

  राजस्थान के वन क्षेत्र सीमित हैं, लेकिन **पर्यावरणीय स्थिरता और सतत आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं।**

5. जल संसाधन

5.1 अवलोकन

- राजस्थान **भारत में सबसे अधिक जल की कमी वाला राज्य है** , जिसके पास **भारत के सतही जल का केवल 1.16%** और **भूजल का 1.72% ही उपलब्ध है** ।
- औसत वार्षिक वर्षा: **~530 मिमी** (स्थानिक रूप से असमान - पश्चिम में 100 मिमी, दक्षिण-पूर्व में 1000 मिमी)।

5.2 प्रमुख नदियाँ

नदी	मूल	प्रवाह	प्रमुख उपयोग
चंबल	विंध्य पर्वतमाला (मध्य प्रदेश)	कोटा, बूंदी	जल विद्युत, सिंचाई।
केले	अरावली पहाड़ियाँ	टोंक , जयपुर	कृषि, पेय.
सोमवार	अरावली पहाड़ियाँ (अजमेर)	बाड़मेर , जालोर	मौसमी, खारा पानी.
माही	मध्य प्रदेश	बांसवाड़ा , डूंगरपुर	जल विद्युत, सिंचाई।
साबरमती	उदयपुर	गुजरात	सिंचाई।

5.3 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ

- **इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी):** सबसे बड़ी नहर प्रणाली, 650 किमी; पश्चिमी राजस्थान में 17 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है।
- **चम्बल घाटी परियोजना:** बहुउद्देश्यीय (कोटा, रावतभाटा बांध)।
- **जवाई और माही बजाज सागर परियोजनाएं:** क्षेत्रीय सिंचाई और जल विद्युत।
- **नर्मदा नहर विस्तार:** सूखाग्रस्त जिलों में जल हस्तांतरण।
  सिंचाई नेटवर्क ने पश्चिमी राजस्थान को बदल दिया, फसलों, पशुधन और बस्ती विस्तार को बढ़ावा दिया।

5.4 जल चुनौतियाँ

- अति-शोषित क्षेत्रों में भूजल की कमी और लवणता।
- रेगिस्तानी जिलों (बाड़मेर , जैसलमेर) में जल संकट।
- चल रहे कार्यक्रम: **जल जीवन मिशन** , **मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन** जल संचयन के लिए **अभियान (एमजेएसए) ।**
  सतत जल प्रबंधन **राजस्थान की भावी अर्थव्यवस्था की आधारशिला बना हुआ है।**

6. ऊर्जा संसाधन और क्षमता

6.1 पारंपरिक ऊर्जा

- **लिग्नाइट आधारित बिजली:** बाड़मेर , गिरल , बीकानेर।
- **जलविद्युत:** चंबल नदी प्रणाली, माही बजाज सागर ।
- **थर्मल पावर:** कोटा, सूरतगढ़ , छबड़ा थर्मल स्टेशन।

6.2 नवीकरणीय ऊर्जा

स्रोत	संभावना	प्रमुख स्थान	स्थिति
सौर ऊर्जा	142 गीगावाट क्षमता	भादला (जोधपुर), जैसलमेर, बाड़मेर	विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क (भड़ला)।
पवन ऊर्जा	18 गीगावाट क्षमता	जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर	पवन ऊर्जा क्षमता में भारत में दूसरे स्थान पर।
बायोमास / बायोगैस	5 गीगावाट क्षमता	टोंक , भरतपुर , अलवर	ग्रामीण ऊर्जा विविधीकरण।

राजस्थान **भारत की नवीकरणीय ऊर्जा राजधानी है** , जो इसके सतत विकास मॉडल की आधारशिला है।

7. पर्यावरण और संसाधन प्रबंधन मुद्दे

संसाधन	प्रमुख मुद्दा	नीति प्रतिक्रिया
भूमि	मरुस्थलीकरण और मृदा अपरदन	एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), एमजीएनआरईजीएस।
पानी	अति-निष्कर्षण और कमी	एमजेएसए, जल जीवन मिशन, नहरों को आपस में जोड़ना।
खनिज पदार्थ	वातावरण संबंधी मान भंग	सतत खनन नीति, सीएसआर दायित्व।
जंगलों	वनों की कटाई, चराई का दबाव	जेएफएम, कैम्पा फंड, वनीकरण।
ऊर्जा	संचरण अकुशलता	ग्रीन कॉरिडोर परियोजनाएं, सौर पार्क।

राजस्थान का टिकाऊ भविष्य **पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना और कुशल संसाधन प्रबंधन पर निर्भर करता है** ।

8. PYQ एकीकरण

8.1 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

- राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों और उनके आर्थिक महत्व पर चर्चा करें।
- राजस्थान में खनिज संसाधनों के महत्व एवं चुनौतियों की व्याख्या कीजिए।
- राज्य में प्रमुख सिंचाई एवं जल प्रबंधन परियोजनाएँ कौन-कौन सी हैं?
- नवीकरणीय ऊर्जा विकास में राजस्थान की क्षमता का मूल्यांकन करें।

8.2 PYQ रुझान
- **आरपीएससी/आईएएस:** खनिज, जल संसाधन और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें।
- **यूजीसी-नेट:** प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को विकास नीति से जोड़ने वाले विश्लेषणात्मक प्रश्न।

9. सारांश नोड
- राजस्थान का **प्राकृतिक संसाधन आधार** समृद्ध और विविध है - खनिज और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमुख परिसंपत्तियां हैं, जबकि **भूमि और जल की कमी** बाध्यकारी बाधाएं बनी हुई हैं।
- टिकाऊ ग्रामीण आजीविका के लिए **मिट्टी, जल और वन संसाधनों** का उचित प्रबंधन महत्वपूर्ण है।
- **खनिज आधारित विकास से हरित ऊर्जा नेतृत्व** की ओर राज्य का संक्रमण एक रणनीतिक विकास बदलाव का प्रतीक है। राजस्थान का आर्थिक भाग्य **पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संसाधन उपयोग को संतुलित करने में निहित है।**

राजस्थान के मानव संसाधन: जनसांख्यिकी प्रोफ़ाइल, कार्यबल, शिक्षा और मानव विकास

1. परिचय

1.1 आर्थिक पूंजी के रूप में मानव संसाधन
- मानव संसाधन **आर्थिक विकास का सबसे गतिशील और उत्पादक कारक है** ।
- राजस्थान की अर्थव्यवस्था, यद्यपि खनिजों और भूमि से समृद्ध है, लेकिन **मध्यम मानव विकास संकेतकों** और **कम कौशल स्तरों द्वारा सीमित है** ।
- समावेशी विकास के लिए **शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल संवर्धन** के माध्यम से अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करना आवश्यक है।
  राजस्थान का वास्तविक संसाधन उसके लोग हैं - जनसंख्या को उत्पादक मानव पूंजी में परिवर्तित करना प्रमुख चुनौती बनी हुई है।

2. राजस्थान की जनसांख्यिकीय रूपरेखा

सूचक	2001	2011	2024 (अनुमानित)	अवलोकन
जनसंख्या (करोड़ में)	5.64	6.86	8.12	स्थिर वृद्धि (1.6% सीएजीआर).
घनत्व (प्रति वर्ग किमी)	165	200	215	राष्ट्रीय औसत (464) से कम.
लिंग अनुपात (f/1000 मीटर)	921	928	944	धीरे-धीरे सुधार.
साक्षरता दर (%)	61.0	66.1	72.8	लिंग भेद कायम है।
शहरीकरण (%)	23.4	24.9	29.5	जयपुर, कोटा, जोधपुर में तेजी।
अनुसूचित जाति जनसंख्या (%)	17.8	18.1	~18	महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय हिस्सा.
अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (%)	12.6	13.5	~14	दक्षिणी जिलों में केन्द्रित।

राजस्थान की जनसंख्या **मुख्यतः ग्रामीण और युवा है** , जिससे नौकरियों और बुनियादी ढांचे पर संभावना और दबाव दोनों बढ़ रहे हैं।

Unleash the topper in you

3. जनसांख्यिकीय विशेषताएं और चुनौतियाँ

3.1 जनसंख्या वृद्धि
- अभी भी प्रतिस्थापन दर से ऊपर; जनजातीय और पश्चिमी जिलों में उच्च।
- **भूमि और जल संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव** गरीबी और बेरोजगारी में योगदान देता है।

3.2 आयु संरचना
- युवा (15-34 वर्ष): जनसंख्या का ~36% - जनसांख्यिकीय लाभांश चरण।
- हालाँकि, केवल **40% युवा ही औपचारिक रूप से कुशल हैं** , जो श्रम बल में **कौशल की कमी को दर्शाता है।**

3.3 लैंगिक असमानताएँ
- महिला साक्षरता ~62% बनाम पुरुष 82%.
- महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर): ~27% (2023-24)।
- सामाजिक मानदंड, अवैतनिक कार्य और अनौपचारिक रोजगार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को सीमित करते हैं।
  कौशल, लिंग समावेशन और शिक्षा सुधारों के बिना राजस्थान का जनसांख्यिकीय लाभ एक दायित्व बन सकता है ।

4. श्रम बल और रोजगार विशेषताएँ

4.1 श्रम बल भागीदारी

सूचक	ग्रामीण (%)	शहरी (%)	कुल (%)
पुरुष एलएफपीआर	78	68	74
महिला एलएफपीआर	33	20	27
समग्र एलएफपीआर	57	44	52

- अधिकांश कार्यबल **अनौपचारिक है और कृषि एवं निर्माण क्षेत्र** में केंद्रित है ।
- शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों (जयपुर, भिवाड़ी , उदयपुर, कोटा) की ओर बढ़ता प्रवास।

4.2 रोजगार संरचना

क्षेत्र	रोजगार हिस्सेदारी (%)	टिप्पणी
कृषि एवं संबद्ध	54	प्रभुत्व, कम उत्पादकता.
उद्योग	21	एमएसएमई और विनिर्माण के साथ विस्तार।
सेवाएं	25	पर्यटन, व्यापार, शिक्षा आधारित।

रोजगार की स्थिति **ग्रामीण और कृषि प्रधान बनी हुई है** , तथा अल्प-रोजगार एक सतत समस्या बनी हुई है।

5. शिक्षा और कौशल विकास

5.1 शैक्षिक अवसंरचना

स्तर	महत्वपूर्ण संकेतक	टिप्पणी
प्राथमिक शिक्षा	जीईआर ~99%	पहुंच में सुधार हुआ; गुणवत्ता संबंधी समस्याएं बनी रहीं।
माध्यमिक शिक्षा	जीईआर ~80%	स्कूल छोड़ने की दर अभी भी ऊंची है, विशेषकर लड़कियों के लिए।
उच्च शिक्षा	~350 कॉलेज, 60+ विश्वविद्यालय	2010 के बाद निजी विश्वविद्यालयों का विस्तार।
तकनीकी शिक्षा	250 से अधिक पॉलिटेक्निक, 75 आईटीआई का उन्नयन	कौशल भारत कार्यक्रम से जुड़ा हुआ।

5.2 कौशल विकास पहल

योजना	क्रियान्वयन एजेंसी	उद्देश्य
राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी)	राज्य सरकार	कौशल प्रशिक्षण और रोजगार योग्यता।
दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र	विश्वविद्यालयों	कौशल-एकीकृत उच्च शिक्षा।
कौशल राजस्थान मिशन	आरएसएलडीसी + एनएसडीसी	एकीकृत प्रशिक्षण और प्रमाणन।
अटल नवाचार मिशन और आईटीआई	नीति आयोग / डीटीई	उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देना।

राजस्थान के कौशल कार्यक्रमों का उद्देश्य **शिक्षा-रोजगार के बीच के अंतर को पाटना है** , लेकिन मांग में संतुलन अभी भी कम है।

6. मानव विकास प्रोफ़ाइल

6.1 मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)

वर्ष	मानव विकास सूचकांक मूल्य	राष्ट्रीय रैंक	टिप्पणी
2005	0.55	15 वीं	निम्न सामाजिक संकेतक.
2011	0.61	13 वीं	कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से सुधार।
2022	0.66	11 वीं	शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, लेकिन लिंग भेद अभी भी कायम है।

राजस्थान की मानव विकास सूचकांक वृद्धि सराहनीय है, लेकिन इसके आर्थिक संसाधनों को देखते हुए यह **क्षमता से कम है ।**

6.2 स्वास्थ्य संकेतक

सूचक	2005	2011	2023-24	अवलोकन
शिशु मृत्यु दर (आईएमआर)	65	47	32	एनआरएचएम, जननी सुरक्षा योजना के कारण तेजी से गिरावट ।
मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर)	445	255	163	सुधार हुआ है, फिर भी राष्ट्रीय औसत से ऊपर है।
जीवन प्रत्याशा (वर्ष)	63	67	70	निरंतर सुधार.
संस्थागत प्रसव (%)	45	72	91	मजबूत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विस्तार।

सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों और महिला-केंद्रित कार्यक्रमों से परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

7. प्रवासन और शहरीकरण के रुझान

- पश्चिमी और दक्षिणी जिलों से गुजरात, दिल्ली और हरियाणा की ओर उच्च **मौसमी और संकटपूर्ण प्रवास ।**
- शिक्षा, व्यापार और सेवाओं के कारण जयपुर, कोटा, अजमेर और जोधपुर में **शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है ।**
- ग्रामीण-शहरी प्रवास **कृषि संकट और औद्योगिक अवसरों से जुड़ा हुआ है** ।
  प्रवासन एक **सुरक्षा वाल्व** और **विकास चुनौती दोनों बन गया है** - जिससे ग्रामीण श्रम समाप्त हो रहा है और शहरी दबाव बढ़ रहा है।

8. मानव संसाधन विकास के लिए सरकारी पहल

कार्यक्रम	फोकस क्षेत्र	प्रभाव
मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना	युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण	10 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।
शिक्षा सेतु मिशन	स्कूल का बुनियादी ढांचा और स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी	माध्यमिक शिक्षा प्रतिधारण में सुधार।
मुख्यमंत्री निशुल्क दावा और जंच योजना	निःशुल्क दवाइयाँ और निदान	स्वास्थ्य तक पहुंच को बढ़ावा मिला।
मिशन अनुप्रति	कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग और छात्रवृत्ति	उच्च शिक्षा समावेशन को बढ़ावा देता है।
राजस्थान भामाशाह योजना	कल्याणकारी लाभों के लिए महिला-केंद्रित डीबीटी	वित्तीय सशक्तिकरण और समावेशन।

मानव पूंजी विकास **राजस्थान की सामाजिक नीति संरचना का मूल है** ।

9. मानव संसाधन विकास में चुनौतियाँ

चुनौती	विवरण
कम कौशल तीव्रता	कार्यबल में अकुशल और अनौपचारिक नौकरियों का प्रभुत्व है।
लैंगिक असमानता	लगातार महिला ड्रॉपआउट और कम FLFPR.
क्षेत्रीय असमानताएँ	जनजातीय और रेगिस्तानी जिले साक्षरता और स्वास्थ्य के मामले में पिछड़े हुए हैं।
स्वास्थ्य अवसंरचना में अंतराल	ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है।
प्रवासन दबाव	शहरी भीड़ और ग्रामीण जनसंख्या में कमी।

समावेशी विकास के लिए **शैक्षिक गुणवत्ता, स्वास्थ्य पहुंच और कौशल संरेखण को** जोड़ना आवश्यक है।

10. PYQ एकीकरण

10.1 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

- राजस्थान की जनसांख्यिकीय एवं मानव संसाधन विशेषताओं पर चर्चा कीजिए।
- राजस्थान की मानव विकास स्थिति एवं क्षेत्रीय असमानताओं का मूल्यांकन कीजिए।
- राजस्थान की मानव पूंजी का उपयोग करने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?
- राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के लिए सरकारी पहलों का वर्णन करें।

10.2 PYQ रुझान

- **आरपीएससी/आईएएस:** जनसांख्यिकी को विकास से जोड़ने वाले विश्लेषणात्मक प्रश्न।
- **यूजीसी-नेट:** डेटा-आधारित और एचडीआई तुलनात्मक प्रश्न।

11. सारांश नोड

- राजस्थान के मानव संसाधन में **युवा गतिशीलता तो है** , लेकिन **कौशल और लिंग समावेशन सीमित है** ।
- शिक्षा और स्वास्थ्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, फिर भी क्षेत्रीय और सामाजिक स्तर पर असमानताएं बनी हुई हैं।
- राज्य का भावी विकास शिक्षा, कौशल और कल्याण तालमेल के माध्यम से **अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को उत्पादक रोजगार में परिवर्तित करने पर निर्भर करता है।**

  मानव विकास, राजस्थान की संसाधन-आधारित अर्थव्यवस्था से ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए **रणनीतिक धुरी है।**

राजस्थान में कृषि: प्रकृति, फसल पद्धति और उत्पादकता रुझान

1. परिचय

1.1 राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में कृषि

- **राजस्थान के** लगभग 55% कार्यबल के लिए कृषि **प्रमुख व्यवसाय और आजीविका का स्रोत बना हुआ है** ।
- **राज्य के जीएसडीपी (2023-24) में** लगभग 23-25% का योगदान देता है ।
- **फसल विविधीकरण, सिंचाई और कृषि-औद्योगिक एकीकरण** में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है ।

  राजस्थान की कृषि प्रतिकूल परिस्थितियों में समृद्धि के विरोधाभास को दर्शाती है - जो जलवायु अनिश्चितता के बीच भी फलती-फूलती है।

2. राजस्थान में कृषि की प्रकृति एवं विशेषताएँ

विशेषता	विवरण
जलवायु पर निर्भरता	अर्द्ध शुष्क से शुष्क; वर्षा अत्यधिक अनियमित (औसत 530 मिमी).
प्रमुख वर्षा आधारित खेती	लगभग 65% फसल क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है।
कम उत्पादकता	मृदा और जल संबंधी बाधाओं के कारण राष्ट्रीय औसत से नीचे।
निर्वाह-सह-व्यावसायिक खेती	खाद्यान्न से तिलहन और नकदी फसलों की ओर बदलाव।
क्षेत्रीय भिन्नता	पूर्वी नहर-सिंचित क्षेत्रों में उत्पादकता उच्च; पश्चिमी रेगिस्तान में कम।
दोहरी कृषि प्रणाली	पारंपरिक तकनीकें मशीनीकृत खेती के साथ-साथ मौजूद हैं।

राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था **विविधतापूर्ण, जोखिमपूर्ण है तथा** प्रौद्योगिकी और सिंचाई विस्तार के माध्यम से विकसित हो रही है।

3. राजस्थान के कृषि-जलवायु क्षेत्र

क्षेत्र	जिले (प्रमुख)	विशेषताएँ / प्रमुख फसलें
I. पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र	जैसलमेर, बाड़मेर , बीकानेर	बाजरा , ग्वार, मोठ, ग्वार, पशुधन।
II. Transitional Plains (NW)	Nagaur, Sikar, Jhunjhunu	Wheat, mustard, barley, pulses.
III. Semi-Arid Eastern Plains	Jaipur, Alwar, Bharatpur	Wheat, mustard, maize, cotton.
IV. Southern Humid Zone	Udaipur, Dungarpur, Banswara	Maize, rice, pulses, fruits.
V. Southeastern (Black Soil)	Kota, Bundi, Baran, Jhalawar	Soybean, wheat, cotton, rice.

कृषि-क्षेत्रीय विविधता राजस्थान की **बहु-फसलीय और क्षेत्रीय नीति दृष्टिकोण को परिभाषित करती है** ।

4. भूमि उपयोग और फसल तीव्रता

पैरामीटर	2000-01	2010-11	2023-24
शुद्ध बोया गया क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)	20.0	20.7	21.2
सकल फसल क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)	26.2	28.1	29.6
फसल की तीव्रता (%)	131	136	140

- **सिंचाई और मशीनीकरण** से भूमि उपयोग में सुधार हुआ ।
- **परती भूमि और बंजर भूमि सुधार से** विस्तार में योगदान मिला।

राजस्थान की फसल सघनता में लगातार वृद्धि हुई है, जो **बेहतर भूमि उपयोग दक्षता का संकेत है** ।

5. फसल पैटर्न

5.1 प्रकार के अनुसार प्रमुख फसलें

फसल का प्रकार	प्रमुख फसलें	फसल क्षेत्र में हिस्सा	नोट्स
खाद्यान्न	बाजरा , गेहूं, मक्का, जौ	55%	शुष्क पश्चिम में बाजरा की खेती प्रमुख है, जबकि सिंचित पूर्व में गेहूं की खेती प्रमुख है।
तिलहन	सरसों, मूंगफली, तिल	20%	सरसों = प्रमुख नकदी फसल (भारत में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक)।
वाणिज्यिक फसलें	कपास, ग्वार गम, सोयाबीन	10%	निर्यात क्षमता और कृषि-औद्योगिक संबंध।
दालें	चना, मोठ, मूंग	10%	मिट्टी की उर्वरता के लिए महत्वपूर्ण.
फल सब्जियां	अमरूद, खट्टे फल, प्याज, टमाटर	5%	परि -नगरीय और जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ रहा है ।

राजस्थान **भारत में बाजरा , सरसों और ग्वार गम का सबसे बड़ा उत्पादक है** , जो शुष्क पारिस्थितिकी के अनुकूलन को दर्शाता है।

6. फसल में क्षेत्रीय विविधता

क्षेत्र	प्रमुख फसलें	टिप्पणी
पश्चिमी राजस्थान	बाजरा , ग्वार, मोठ, मूंग	वर्षा आधारित, सूखा सहनशील फसलें।
पूर्वी मैदान	गेहूं, सरसों, जौ	नहर-सिंचित कृषि.
दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र	सोयाबीन, कपास, मक्का	काली मिट्टी उर्वरता, मानसून-सिंचित।
जनजातीय दक्षिण	मक्का, चावल, दालें	वर्षा आधारित पहाड़ी खेती; स्थानान्तरित खेती वाले क्षेत्र।

फसल पद्धति **वर्षा, मिट्टी के प्रकार और सिंचाई की सुविधा द्वारा निर्देशित होती है।**

Toppersnotes
Unleash the topper in you

7. सिंचाई और कृषि आधुनिकीकरण

7.1 सिंचाई कवरेज

स्रोत	शेयर करना (%)	टिप्पणी
नहर सिंचाई	35	इंदिरा गांधी नहर, चंबल परियोजना।
कुएँ और ट्यूबवेल	55	भूजल का प्रभुत्व, अति-शोषण।
टैंक और अन्य	10	वर्षा जल संचयन, एमजेएसए पहल।

- कुल सिंचित क्षेत्र: ~8.5 मिलियन हेक्टेयर (2023-24)।
- नहर नेटवर्क और सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली) के माध्यम से **सिंचाई की तीव्रता में सुधार हुआ।**

  राजस्थान शुष्क परिस्थितियों में **जल-कुशल सिंचाई में अग्रणी है।**

8. कृषि उत्पादकता के रुझान

काटना	उपज (किग्रा/हेक्टेयर) - 2000-01	2010-11	2023-24	रुझान
बाजरे	880	1080	1250	संकर के माध्यम से सुधार किया गया।
गेहूँ	2480	3050	3600	भरतपुर में उच्च उपज क्षेत्र ।
सरसों	1100	1340	1620	प्रमुख नकदी फसल; इनपुट-प्रधान।
ग्राम	900	1050	1250	स्थिर पैदावार, मिट्टी की उर्वरता की भूमिका।
सोयाबीन	1250	1400	1500	दक्षिण-पूर्व क्षेत्र में विस्तार.

सिंचाई, उच्च उपज वाले वाहनों, उर्वरकों और मशीनीकरण से उत्पादकता में वृद्धि हुई है , फिर भी क्षेत्रीय असमानता बनी हुई है।

9. कृषि यंत्रीकरण और इनपुट

- **ट्रैक्टर:** 7.5 लाख से अधिक ट्रैक्टर उपयोग में हैं; सिंचित जिलों में मशीनीकरण व्यापक है।
- **उर्वरक उपयोग:** ~135 किग्रा/हेक्टेयर (राष्ट्रीय औसत 150 से कम)।
- **उच्च उपज वाले बीज:** गेहूं, सरसों और कपास में 60-70% कवरेज।
- **कीटनाशक एवं कृषि रसायन:** सिंचित क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है; जैविक पद्धतियों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है।

9.1 कृषि प्रौद्योगिकी और विस्तार

- **कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके)** - अनुसंधान-से-क्षेत्र संपर्क को बढ़ावा देने वाले 45 केन्द्र ।
- **राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर** - फसल अनुसंधान एवं जलवायु अनुकूलन।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना** - किसानों को पोषक तत्व आधारित सलाह।

  विज्ञान आधारित कृषि की ओर बदलाव राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण विकास है।

10. जलवायु और संरचनात्मक बाधाएँ

बाधा	स्पष्टीकरण
पानी की कमी	वर्षा की अनिश्चितता; भूजल की कमी।
भूमि विखंडन	छोटी जोतें मशीनीकरण को सीमित करती हैं।
मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण	40% भूमि क्षेत्र प्रभावित होता है।
कम ऋण पहुंच	अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता.
बाजार अस्थिरता	तिलहन और दालों की कीमतों में अस्थिरता।

राजस्थान में कृषि **पारिस्थितिक रूप से नाजुक** और **आर्थिक रूप से कमजोर है** ।

11. कृषि विकास के लिए सरकारी पहल

योजना / मिशन	उद्देश्य
राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता परियोजना (आरएसीपी)	उत्पादकता वृद्धि, बाजार संपर्क।
कृषि मिशन 2022 और 2025	किसानों की आय दोगुनी करना; विविधीकरण।
पीएम-किसान	छोटे किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता।
राजस्थान राज्य बीज निगम	एचवाईवी प्रसार.
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)	ग्रामीण ऋण सुलभता।
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (एमजेएसए)	जल संचयन और सूखा निवारण।
जैविक खेती मिशन	पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा दें।

राजस्थान की कृषि नीति में **स्थिरता, प्रौद्योगिकी और कल्याण का मिश्रण है** ।

ToppersNotes
Unleash the topper in you

12. PYQ एकीकरण

12.1 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

- राजस्थान में कृषि की प्रकृति एवं संरचना की व्याख्या कीजिए।
- कृषि में फसल पैटर्न और क्षेत्रीय विविधताओं का वर्णन करें।
- राजस्थान में कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए।
- कृषि विकास में सिंचाई और आधुनिकीकरण की भूमिका का मूल्यांकन करें।

12.2 PYQ रुझान

- **आरपीएससी/आईएएस:** क्षेत्रीय विश्लेषण एवं सिंचाई आधारित कृषि।
- **यूजीसी-नेट:** फसल वितरण, डेटा-आधारित रुझान और आधुनिकीकरण प्रभाव।

13. सारांश नोड

- कृषि **राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनी हुई है** , जो आजीविका को सहारा देती है तथा जीएसडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
- फसल पैटर्न **पारिस्थितिक विविधता के प्रति अनुकूलन** और तिलहन और नकदी फसलों के माध्यम से **बाजार एकीकरण को प्रदर्शित करता है।**
- सिंचाई विस्तार और मशीनीकरण से उत्पादकता में सुधार हुआ है, लेकिन **जल की कमी, विखंडन और बाजार जोखिम** अभी भी बने हुए हैं।
- कृषि का भविष्य **जलवायु-अनुकूल, प्रौद्योगिकी-संचालित और विविध कृषि प्रणालियों में निहित है।**

राजस्थान में कृषि सुधार, योजनाएँ और नवाचार

1. परिचय

1.1 कृषि सुधारों का विकास

- राजस्थान का कृषि परिवर्तन **भूमि सुधार, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, सिंचाई विस्तार और प्रौद्योगिकी सम्मिलन के माध्यम से विकसित हुआ है।**
- सुधार का लक्ष्य **भूमि पुनर्वितरण (1950-70 के दशक) से बाजार-संचालित, उत्पादकता-उन्मुख और सतत विकास (1990 के दशक-वर्तमान)** में स्थानांतरित हो गया है।
- हालिया फोकस: किसानों की आय दोगुनी करना, जलवायु लचीलापन और जल दक्षता।
  राजस्थान में सुधार की यात्रा भारत के कृषि विकास को प्रतिबिंबित करती है - पुनर्वितरण से लेकर लचीलेपन और स्थिरता तक।

2. राजस्थान में भूमि सुधार

2.1 उद्देश्य

- बिचौलियों का उन्मूलन, भूमि का पुनर्वितरण, काश्तकारी विनियमन और जोतों का समेकन।

2.2 प्रमुख विधायी उपाय

अधिनियम / वर्ष	उद्देश्य	प्रभाव
राजस्थान जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम, 1952	बिचौलियों को समाप्त किया गया, भूमि काश्तकारों को हस्तांतरित की गई।	सामंती प्रभुत्व में कमी; किसानों को सशक्त बनाया गया।
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955	किरायेदारी को विनियमित किया गया, किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा की गई, उचित किराया सुनिश्चित किया गया।	भूमि सुरक्षा में वृद्धि।
राजस्थान कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1973	भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई (लगभग 18-54 एकड़, सिंचाई पर निर्भर)।	~7.5 लाख हेक्टेयर भूमि का पुनर्वितरण।
भूमि चकबंदी अधिनियम, 1954	खंडित जोतों के समेकन को बढ़ावा दिया गया।	मशीनीकरण और उत्पादकता में सुधार।

भूमि सुधारों ने आधुनिक कृषि के लिए **संस्थागत आधार तैयार किया** , लेकिन सामंती और आदिवासी क्षेत्रों में **कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ा।**

3. सहकारी आंदोलन और ग्रामीण ऋण

3.1 सहकारी ढांचा

स्तर	संस्था	समारोह
प्राथमिक स्तर	PACS (प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ)	अल्पावधि ऋण, इनपुट वितरण।
जिला स्तर	डीसीसीबी (जिला केंद्रीय सहकारी बैंक)	PACS और शीर्ष बैंक के बीच संबंध।
राज्य स्तर	राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (एपेक्स बैंक)	नीति समन्वय, पुनर्वित्तपोषण।

3.2 प्रमुख उपलब्धियाँ
- 5,400+ PACS परिचालन (2024)।
- ग्रामीण ऋण का लगभग 70% सहकारी प्रणाली के माध्यम से प्राप्त होता है।
- सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक, बीज और कीटनाशक वितरण को एकीकृत किया गया।

3.3 चुनौतियाँ
- अतिदेय ऋण, दोहरा नियंत्रण, कम वसूली और कमजोर वित्तीय अनुशासन।
- वाणिज्यिक एवं सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा।
  सहकारिताएं ग्रामीण वित्त की **संस्थागत रीढ़ बनी हुई हैं, लेकिन इन्हें आधुनिकीकरण और डिजिटल एकीकरण की आवश्यकता है।**

4. कृषि ऋण और बीमा
4.1 संस्थागत स्रोत

स्रोत	शेयर करना (%)	टिप्पणी
वाणिज्यिक बैंक	55	केसीसी, फसल ऋण और स्वयं सहायता समूह।
सहकारी बैंक	30	पारंपरिक और ग्रामीण पहुंच।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	10	छोटे और सीमांत किसानों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
गैर-संस्थागत (साहूकार)	5	अभी भी आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित है।

4.2 ऋण योजनाएँ
- **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी):** आसान चक्रीय ऋण; 60 लाख से अधिक कार्ड जारी।
- **ब्याज अनुदान योजना:** शीघ्र पुनर्भुगतान के लिए 3% प्रोत्साहन।
- **नाबार्ड पुनर्वित्त सहायता:** दीर्घकालिक सिंचाई और कृषि मशीनीकरण ऋण।
- **राजस्थान ग्रामीण बैंक एवं सहकारी एकीकरण:** ग्रामीण ऋण पहुंच का विस्तार।
  ऋण उपलब्धता में विस्तार हुआ है, फिर भी इनपुट लागत में वृद्धि के कारण ऋण पर निर्भरता बनी हुई है।

4.3 कृषि बीमा

योजना	कवरेज	केंद्र
पीएम फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	~85 लाख किसान (2024)	प्राकृतिक आपदाओं से जोखिम संरक्षण।
मौसम आधारित फसल बीमा (WBCIS)	चयनित जिले	जलवायु से जुड़े भुगतान.
राज्य फसल क्षतिपूर्ति योजना	पूरक बीमा कवरेज	ऋणी किसानों के लिए राहत ।

फसल बीमा कवरेज और जलवायु जोखिम न्यूनीकरण में राजस्थान भारत के शीर्ष राज्यों में से एक है ।

5. कृषि विपणन और मूल्य नीति
5.1 एपीएमसी और बाजार सुधार
- **राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961:** व्यापार को विनियमित करता है और किसानों को शोषण से बचाता है।
- जिलों में 150 से अधिक एपीएमसी और उप-यार्ड कार्यरत हैं।
- **ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार):** 50 से अधिक मंडियां ऑनलाइन ट्रेडिंग के साथ एकीकृत।
  डिजिटल प्लेटफॉर्म ने किसानों के लिए **मूल्य पारदर्शिता** और **बाजार पहुंच में सुधार किया।**

5.2 न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और खरीद
- गेहूं, सरसों, बाजरा और चना के लिए एमएसपी लागू किया गया।
- **राजफैड** और **भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)** के माध्यम से खरीद ।
- पूर्वी और सिंचित जिलों में एमएसपी परिचालन स्थिर है, जबकि शुष्क पश्चिमी क्षेत्रों में सीमित है।
  मूल्य नीति **क्षेत्रीय स्तर पर असमान बनी हुई है** , जो बुनियादी ढांचे में अंतराल को उजागर करती है।

6. सिंचाई और जल-उपयोग दक्षता पहल
6.1 प्रमुख कार्यक्रम

कार्यक्रम	उद्देश्य
कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सीएडीपी)	नहर क्षेत्रों में कुशल जल प्रबंधन।
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	" हर खेत को पानी " - सिंचाई कवरेज का विस्तार।
ड्रिप और स्प्रिंकलर सब्सिडी योजनाएं	शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण।
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (एमजेएसए)	वर्षा जल संचयन और सामुदायिक जल संरचनाएं।

सूक्ष्म सिंचाई अपनाने में अग्रणी है , जहां 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली अपनाई गई है।

7. कृषि अनुसंधान और नवाचार

संस्था	जगह	केंद्र
स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (बीकानेर)	बीकानेर	शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, फसल किस्में।
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (उदयपुर)	उदयपुर	पहाड़ी कृषि और कृषि मशीनीकरण।
श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय (जोबनेर)	जयपुर	शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान.
कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके)	45 केंद्र	किसान प्रशिक्षण और प्रदर्शन.

7.1 तकनीकी नवाचार

- **सूखा-सहिष्णु बीज किस्में** (बाजरा , ग्वार, सरसों)।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम:** मृदा-विशिष्ट पोषक तत्व प्रबंधन।
- **कृषि-मौसम सलाहकार सेवाएँ (एएमएफयू):** मौसम-आधारित मार्गदर्शन।
- **स्मार्ट खेती पायलट:** सिंचाई और उपज निगरानी के लिए IoT सेंसर।

  नवाचार ने राजस्थान की नाजुक पारिस्थितिकी में **जलवायु-स्मार्ट और सटीक कृषि को संभव बनाया है।**

8. सतत और जैविक कृषि पहल

कार्यक्रम	उद्देश्य
राजस्थान जैविक खेती नीति (2016)	पर्यावरण अनुकूल और रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा दें।
परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)	क्लस्टर आधारित जैविक उत्पादन।
कृषि वानिकी और बागवानी विस्तार	फसल विविधीकरण और मृदा कायाकल्प।
राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना	शुष्क क्षेत्रों में एकीकृत संसाधन प्रबंधन।

राजस्थान का स्थायित्व पर ध्यान **पारिस्थितिकी, आजीविका और दीर्घकालिक लचीलेपन को एकीकृत करता है।**

9. संस्थागत और नीतिगत ढांचा

नीति / संस्थान	वर्ष	मुख्य उद्देश्य
राजस्थान की कृषि नीति	2013	उत्पादकता, विविधीकरण, किसान आय।
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड	1963	व्यापार और बुनियादी ढांचे को विनियमित करें।
राजस्थान कृषि मिशन	2022	कृषि-व्यवसाय और मूल्य-श्रृंखला एकीकरण।
कृषि प्रसंस्करण नीति	2019	खाद्य प्रसंस्करण एवं निर्यात संवर्धन।

नीतियों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए **बाजार एकीकरण और कृषि -औद्योगिक संबंधों पर जोर दिया गया है।**

10. सुधारों का प्रभाव

सूचक	2000	2010	2023	अवलोकन
कृषि विकास (%)	3.4	4.8	5.7	उत्पादकता में वृद्धि की प्रवृत्ति.
सिंचित क्षेत्र (%)	29	37	41	बेहतर कार्यकुशलता.
उर्वरक खपत (किग्रा/हेक्टेयर)	95	115	135	मध्यम तीव्रता.
कृषि मशीनीकरण सूचकांक	0.32	0.47	0.61	तीव्र आधुनिकीकरण.

कृषि सुधारों से **उत्पादकता में स्थिर वृद्धि** और **संस्थागत लचीलापन प्राप्त हुआ है** , यद्यपि असमानता बनी हुई है।

11. चुनौतियाँ

चुनौती	विवरण
खंडित होल्डिंग्स	मशीनीकरण दक्षता कम हो जाती है.
जलवायु परिवर्तनशीलता	बार-बार सूखा, तापमान में अत्यधिक वृद्धि।
कम कृषि लाभप्रदता	बढ़ती इनपुट लागत, स्थिर कीमतें।
सीमित बाजार अवसंरचना	भंडारण और रसद संबंधी कमियां।
ऋण असमानता	छोटे किसानों को औपचारिक वित्त से कम सुविधा मिलती है।

सुधार एजेंडा को उत्पादन से आय स्थिरता और लचीलेपन की ओर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

12. PYQ एकीकरण

12.1 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

- राजस्थान में किए गए प्रमुख कृषि सुधारों पर चर्चा कीजिए।
- कृषि विकास में सहकारी समितियों और ऋण संस्थाओं की भूमिका की व्याख्या कीजिए।
- सिंचाई और विपणन सुधारों के महत्व का मूल्यांकन करें।
- टिकाऊ कृषि के लिए क्या नवाचार पेश किए गए हैं?